श्री भगवान

बनाम

राजस्थान राज्य

10 मई 2001

(एम.बी. शाह और के.जी. बालकृष्णन, न्यायमूर्तिगण)

दंड संहिता, 1860 – धारा 392, 397, 302 और 57 — डकैती – एक परिवार के पांच लोगों की हत्या – परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि – विचारण न्यायालय द्वारा मौत की सजा का प्रावधान – उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि – अपील पर, दोषसिद्धि बरकरार रखी गई – सजा आरोपी की कम उम्र और मौत की सजा के तहत कारावास के कारण उसकी मानसिक पीड़ा को देखते हुए इसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया – अपराध की प्रकृति को क्रूर और परपीड़क माना गया – इसलिए आरोपी को 20 साल की सजा पूरी होने से पहले रिहा नहीं किया जाएगा – सजा – आजीवन कारावास।

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 – धारा 433(बी) सहपठित 433ए – आजीवन कारावास की प्रयोज्यता – **प्रथम दृष्टया** *इसका मतलब दोषी के प्राकृतिक जीवन की शेष पूरी अवधि के लिए — मृत्युदंड — परिवर्तन — रिहाई– अपराध की प्रकृति को देखते हुए, 14 वर्ष पूरे होने पर अभियुक्त की सजा की अनुमति नहीं है।*

साक्ष्य अधिनियम, 1872 – धारा 114 – चित्रण (ए) – अनुमान– अपराध से जुड़े लेख – अपराध होने के तुरंत बाद वसूली – इस तरह के कब्जे के लिए कोई हिसाब नहीं दिया गया – अभिनिर्धारित, अपराध की धारणा को बढ़ावा देता है – हालांकि, अगर माल बदल जाता है तो धारणा कमजोर हो जाती है।

अपीलकर्ता–अभियुक्त को अभियोजन पक्ष के गवाह–17 के परिवार के पांच सदस्यों की मौत का कारण बनने और उनके घर में डकैती करने के लिए आईपीसी की धारा 302, 392 और 397 के तहत दोषी ठहराया गया था। दोषसिद्धि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित थी कि आरोपी को आखिरी बार मृतक में से एक के साथ देखा गया था; और वह चोट अभियुक्त के शरीर पर पाई गई; और घटना के तुरंत बाद आरोपी की निशानदेही पर एक कुल्हाड़ी, एक खून से सनी शर्ट और मृतक के घर से छीना गया सामान बरामद कर लिया गया। यह साबित हो गया कि आरोपी की अभियोजन पक्ष के गवाह –17 के परिवार के सदस्यों से जान–पहचान थी। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए मौत की सजा दी गई और धारा 392 और 397 आईपीसी के तहत अपराध के लिए सजा सुनाई गई। उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

इस न्यायालय में अपील में, अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी नहीं थी और अभियुक्त के अपराध का अनुमान लगाने के लिए अपर्याप्त थी; और यह कि मृतक के रिश्तेदारों में से एक, अभियोजन पक्ष के गवाह –17 का बयान विश्वसनीय नहीं था क्योंकि उसने जांच अधिकारी (अभियोजन पक्ष के गवाह –23) के समक्ष अपने बयान में अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया था; और अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार था क्योंकि ऐसी संभावना थी कि अधिक हमलावर रहे होंगे, क्योंकि कथित तौर पर विभिन्न हथियारों से मृत व्यक्तियों को कई चोटें पहुंचाई गई थीं; और अपीलकर्ता के अनुरोध पर की गई विभिन्न वसूली संदिग्ध थीं। सजा के सवाल पर, उन्होंने तर्क दिया कि अपीलकर्ता की कम उम्र और मौत की सजा के तहत कारावास के कारण उसकी मानसिक पीड़ा जैसे कारकों को कम करने के मद्देनजर सजा को आजीवन कारावास में बदला जा सकता है।

अपील का निस्तारण करते हुए, न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित: 1. निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया है। मामले के तथ्यों को देखते हुए, अपीलकर्ता के अपराध पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है क्योंकि यह साबित हो गया है कि अपीलकर्ता को घटना से पहले एक मृतक के साथ देखा गया था और अपीलकर्ता की मृतक के परिवार के सदस्यों से जान–पहचान थी।

2. अभियोजन पक्ष के गवाह –17 का बयान अविश्वसनीय नहीं ठहराया जा सकता। उसने अपना बयान दर्ज करने वाले अभियोजन पक्ष के गवाह –23 को अपीलकर्ता का नाम नहीं बताया होगा, क्योंकि पुलिस के सामने बयान देते समय (प्रदर्श पी–8) वह गंभीर मानसिक आघात से गुजर रहा होगा। इसके तुरंत बाद अभियोजन पक्ष के गवाह –23 ने स्वयं अभियोजन पक्ष के गवाह –2 का बयान दर्ज किया और उस बयान में, अपीलकर्ता का नाम उस व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया गया था जिसे आखिरी बार मृतकों में से एक के साथ देखा गया था।

3. यह तथ्य कि घरेलू वस्तुओं का उपयोग अपराध के हथियार के रूप में किया गया था, किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति की संभावना को खारिज करता है। चोटों की प्रकृति से यह भी अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितने हमलावर शामिल थे। यह काफी उचित और संभावित है कि एक हमलावर अकेले ही इतनी अधिक चोटें पहुंचा सकता है, खासकर रात के दौरान जब पीड़ित गहरी नींद में रहे होंगे।

4. बरामदगी के संबंध में अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि बरामदगी का समर्थन करने के लिए और भी पुष्ट सबूत हैं।

5.1. हाल ही में अपराध किए जाने के बाद उसके फलों का कब्ज़ा, इस धारणा के लिए एक मजबूत और उचित आधार प्रदान करता है कि जिस पक्ष के कब्जे में वे पाए गए, वह असली अपराधी था, जब तक कि वह किसी तरह से इस तरह के कब्जे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। उनकी अनिच्छा या कोई उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थता को मजबूत, स्वयं दोषारोपण योग्य साक्ष्य के समान माना जाता है। यदि पक्ष उचित स्पष्टीकरण देता है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया, तो अदालतों के लिए अपराध का अनुमान न लगाना उचित होगा। अनुमान के इस नियम की शक्ति अपराध से संबंधित कब्जे की नवीनता पर निर्भर करती है और यदि समय का अंतराल काफी है, तो अनुमान कमजोर हो जाता है और विशेष रूप से, यदि सामान उस प्रकार का होता है जैसे सामान्य प्रक्रिया में होता है ऐसी चीजें बार–बार बदलती रहती हैं। कोई निश्चित अवधि निश्चित करना संभव नहीं है।

इयरभद्रप्पा @ कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य, [1983] 2 एससीसी 330; *मुकुंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य*, [1997] 10 एससीसी 130 और *गुलाब चंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य,* [1995] 13 एससीसी 574, का उल्लेख किया गया है।

5.2. मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता यह स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि अभियोजन पक्ष के गवाह –17 और उसके परिवार के सदस्यों के विभिन्न सोने के गहने और अन्य सामान उसके कब्जे में कैसे आए। अपीलकर्ता यह भी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि उसके शरीर पर चोटें कैसे आईं और उसकी शर्ट खून से लथपथ कैसे हो गई। तथ्यों और परिस्थितियों में, यह एक उपयुक्त मामला है जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ए) के तहत अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने हत्याएं और डकैती की।

6.1. अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया है। आईपीसी की धारा 392 और 397 के तहत अपराधों के संबंध में, अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि की गई है और कोई अलग सजा नहीं दी गई है।

6.2. धारा 57 आईपीसी में प्रावधान है कि सजा की शर्तों के अंशों की गणना में, आजीवन कारावास को बीस साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। अभियुक्त द्वारा किए गए जघन्य, बर्बर अपराध को ध्यान में रखते हुए, किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त को 20 वर्ष की सजा पूरी होने से पहले रिहा नहीं किया जाना चाहिए।

ए देवेन्द्रन बनाम तमिलनाडु राज्य, **[1997]11 एससीसी 720, भिन्न।**

दलबीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य, **[1979] 3 एससीसी 745 और** *सुभाष चंदर बनाम कृष्ण लाल और अन्य,* **(2001) 3 स्केल 130, संदर्भित।**

6.3. हालाँकि सीआरपीसी की धारा 433 (बी) के साथ पठित धारा 433 (बी) के तहत प्रावधान है, लेकिन अपीलकर्ता को 14 साल की कैद पूरी होने पर रिहा नहीं किया जा सकता है। प्रथम दृष्टया लगाई गई आजीवन कारावास की सजा को दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष पूरी अवधि के लिए कारावास के रूप में माना जाएगा। जेल अधिनियम के तहत बनाए गए नियम आजीवन कारावास की सजा के स्थान पर कम सजा नहीं देते हैं।

मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह और अन्य, **(1976) 3 एससीसी 470;** *मेरु राम बनाम भारत संघ,* **(1981) 1 एससीसी 107;** *लक्ष्मण नस्कर (जीवन दोषी) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य,* **(2000)7 एससीसी 626 और** *गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य,* **(1961) 3 एससीआर 440, संदर्भित।**

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2000 की आपराधिक अपील संख्या 242।

डीबी क्रिमिनल एमआर संख्या 3/98 और डीबी क्रिमिनल जेए संख्या 20 ऑफ 1999 में राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 15.12.99 से।

अपीलकर्ता की ओर से डॉ श्यामला पप्पू, आर कृष्णमूर्ति, एके सिन्हा और शकील अहमद (एसी)।

प्रत्यर्थी की ओर से सुशील कुमार जैन, ए मिश्रा और अंजलि दोशी।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

न्यायाधीश के.जी. बालकृष्णन, द्वारा। इस आपराधिक अपील के तथ्य अद्वितीय बुराई और बर्बरता के कृत्यों का खुलासा करते हैं क्योंकि एक ही परिवार के पांच लोगों को लगभग 20 साल की उम्र के एक युवा अपराधी द्वारा बिना किसी दया के पीट-पीटकर मार डाला गया था।

अभियोजन पक्ष के गवाह -17 शिव प्रताप, उनकी पत्नी, तीन बेटियाँ और वृद्ध माता-पिता बीदासर के एक घर में रहते थे। शिव प्रताप की बड़ी बेटी की शादी 20.2.1994 को होनी तय हुई थी। शादी के लिए कुछ सामान खरीदने के लिए, शिव प्रताप और उनकी पत्नी भंवरी 14 दिसंबर, 1993 को जयपुर के लिए रवाना हुए थे। वे 17 दिसंबर, 1993 को रात लगभग 9.30 बजे जयपुर से बीदासर वापस आए। घर पहुंचने पर उन्हें घर का बाहरी दरवाजा खुला मिला और अंदर के कमरे में अंदर से कुंडी लगी हुई थी। अभियोजन पक्ष के गवाह -17 ने व्यर्थ में दरवाजा खटखटाया और कुछ देर बाद, वह दीवार फांदकर कमरे में प्रवेश कर गया। उसने देखा कि उसके माता-पिता कई चोटों के साथ मृत पड़े थे। अभियोजन पक्ष के गवाह -17 और

उसकी पत्नी फिर अपनी बेटियों के कमरे में गए। वह कमरा बाहर से बंद पाया गया. अभियोजन पक्ष के गवाह –17 ने ताला तोड़ा और अपनी तीन बेटियों के शव पाए। कमरे में खून से सने कई सामान बिखरे हुए मिले। अभियोजन पक्ष के गवाह –17 दुकान के सोने और चांदी के आभूषणों से भरे बैग को खूंटी में रखता था। वह बैग भी गायब मिला। घटना से स्तब्ध होकर उन्होंने शोर मचा दिया। अभियोजन पक्ष के गवाह –17 का भाई जो पास में ही रहता था, घर पर आया। इसी बीच कुछ पड़ोसी भी वहां आ गए और उन्होंने यह भयानक हादसा देखा। लगभग 9.45 बजे तक, अभियोजन पक्ष के गवाह –17 ने पुलिस स्टेशन, छपार के स्टेशन गृह अफ़सर (अभियोजन पक्ष के गवाह –23) के समक्ष पी–8 बयान दिया। अभियोजन पक्ष के गवाह –23 ने मामला दर्ज किया और तुरंत घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने भंवरी (अभियोजन पक्ष के गवाह –1) का बयान दर्ज किया; मुरलीधर (अभियोजन पक्ष के गवाह –2) और शिव प्रताप (अभियोजन पक्ष के गवाह –17) का आगे का बयान भी। अगले दिन, उन्होंने विभिन्न तस्वीरें लीं और सभी पांच मृत व्यक्तियों के शवों की जांच की। घर में पड़े कपड़े समेत विभिन्न सामान बरामद कर लिया गया। इनमें से कई वस्तुएं खून से सने हुए पाए गए।

अपने बयान में, अभियोजन पक्ष के गवाह –2, मुरलीधर ने उल्लेख किया कि 14 दिसंबर, 1993 की शाम को, उन्होंने मृतक जोराराम, पिता शिव प्रताप को लगभग 6.00 बजे दुकान बंद करने के बाद अपने घर जाते हुए देखा था और अपीलकर्ता, उनके साथ श्री भगवान भी थे। अभियोजन पक्ष के गवाह –2 ने आगे कहा कि श्रीभगवान उसे पहले से जानते थे क्योंकि उसने शिव प्रताप की दुकान में लगभग 8 से 10 महीने तक काम किया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने अपीलकर्ता और जोराराम को शिव प्रताप के घर में प्रवेश करते देखा था। इस जानकारी के आधार पर, अपीलकर्ता श्री भगवान को 18 दिसंबर, 1993 की रात को गिरफ्तार कर लिया गया और मामले की जांच अभियोजन पक्ष के गवाह –24 ने अपने हाथ में ले ली। उन्होंने भी घटनास्थल का दौरा किया और वहां से विभिन्न वस्तुएं एकत्र कीं। घटनास्थल से एक टूटा हुआ लोहे का 'कुंटा', एक लकड़ी का मूसल और एक लोहे की कैंची भी बरामद की गई और ये सभी सामान खून से सने हुए थे। अपीलकर्ता से पूछताछ की गई और उसके बयान के आधार पर शिव प्रताप के घर की छत पर स्थित पानी की टंकी से एक कुल्हाड़ी बरामद की गई। आगे की जांच के दौरान, अपीलकर्ता ने शिव प्रताप के घर से लूटे गए सोने के आभूषणों और अन्य सामानों को छुपाने के स्थान के बारे में एक बयान दिया। अपीलकर्ता के बहनोई (बहनोई) रामू राम सरदार शहर के निवासी थे। अपीलकर्ता पुलिस दल को रामू राम के घर तक ले गया और उसके घर से प्रदर्शनी पी–83 के तहत आभूषण और अन्य सामान से भरा एक बैग जब्त किया गया। इन वस्तुओं में एक सोने की अंगूठी, सोने के कान के टॉप और नाक के टॉप, सफेद मोती आदि शामिल थे। बाद में इन सभी वस्तुओं की पहचान शिव प्रताप ने अपनी मां और बेटियों के सोने के आभूषणों के रूप में की। रामू राम के घर से, एक छोटा तंबाकू का डिब्बा बरामद किया गया जिसमें 12 तांबे के टुकड़े और कुमकुर्ण पत्री का एक लिफाफा था जो शिव प्रताप, बीदासर को संबोधित था, और प्रेषक का नाम माणक चंद सोनी (अभियोजन पक्ष के गवाह –10) था। मानक चंद से पूछताछ की गई और उन्होंने गवाही दी कि यह निमंत्रण उन्होंने शिव प्रताप को उनकी बेटी की शादी के अवसर पर भेजा था, जो 10 दिसंबर, 1993 को थी। अपीलकर्ता श्री भगवान ने इस आशय का एक बयान भी दिया कि जब वह बस में यात्रा कर रहा था, तो उसने घटना के समय पहनी हुई शर्ट को सुजानगढ़ से तीन किलोमीटर दूर एक स्थान के पास फेंक दिया था। अपीलकर्ता पुलिस दल को उस स्थान पर ले गया और उक्त शर्ट उस स्थान के पास झाड़ियों से बरामद की गई, जहां अपीलकर्ता ने उसे फेंकने की बात कही थी। यह शर्ट खून से सनी हुई थी और इस पर 786 जेके टेलर्स, सब्जी मंडी का लेबल लगा हुआ था। शर्ट पर 427 संख्या अंकित मिला। जांच अधिकारी ने बाद में जेके टेलर्स की उक्त दुकान का दौरा किया और दुकान के मालिक जफर हुसैन (अभियोजन पक्ष के गवाह –18) से पूछताछ की। अभियोजन पक्ष के गवाह –18 ने कहा कि उसने अपीलकर्ता के लिए शर्ट सिल दी थी और उसने अपीलकर्ता का नाम और माप भी रजिस्टर में दर्ज कर लिया था। प्रदर्श पी–48 उनके द्वारा

संधारित रजिस्टर है तथा क्रमांक 427 के विरूद्ध अपीलार्थी श्रीभगवान सोनी का नाम लिखा हुआ पाया गया।

अपीलकर्ता पर आईपीसी की धारा 302 और 392 के साथ धारा 397 के तहत अपराध के लिए मुकदमा चलाया गया और उसे दोषी पाया गया। आईपीसी की धारा 392 और 397 के तहत अपराध के लिए, उसे सात साल के कठोर कारावास और 200 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। आईपीसी की धारा 302 के तहत अपराध के लिए, अपीलकर्ता को मौत की सजा दी गई और सत्र न्यायाधीश द्वारा 200 रु का जुर्माना अदा किया गया। इसे अपील में चुनौती दी गई और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की।

अपीलकर्ता की ओर से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता (ए.सी.) डॉ. श्यामला पप्पू ने बहुत ही कुशलता से मामले की पैरवी की। उनके द्वारा यह बताया गया कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूत उन अपराधों के लिए अपराध का पता लगाने के लिए पर्याप्त नहीं थे जिनके लिए उन पर आरोप लगाए गए थे। यह तर्क दिया गया कि न्यायालय द्वारा जिन विभिन्न आपत्तिजनक परिस्थितियों पर निर्भर किया गया, वे अपीलकर्ता के अपराध का अनुमान लगाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं और परिस्थितियों की श्रृंखला को ठोस और मजबूती से स्थापित नहीं किया गया था और इन परिस्थितियों में आरोपी के अपराध को स्पष्ट रूप से इंगित करने की कोई निश्चित प्रवृत्ति नहीं है। यह भी तर्क दिया गया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी संपूर्ण होनी चाहिए, कि इस निष्कर्ष से बचा नहीं जा सके कि पूरी संभावना है कि अपराध आरोपी द्वारा किया गया था और किसी और ने नहीं। अपीलकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष के गवाह –17 शिव प्रताप द्वारा दिए गए प्रदर्श पी–8 बयान में, अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था, हालांकि उनके साथ अभियोजन पक्ष के गवाह –2 मुरलीधर भी थे, जिन पर अपीलकर्ता को, घटना से पहले मृतक के साथ देखने का आरोप है। यह ध्यान दिया जा सकता है कि पुलिस के समक्ष प्रदर्श पी–8 बयान देते समय अभियोजन पक्ष के गवाह –17 गंभीर मानसिक आघात से गुजर रहा होगा और स्वाभाविक रूप से उसने अभियोजन पक्ष के गवाह –23 को अपीलकर्ता के नाम का उल्लेख नहीं किया जिसने उसका बयान दर्ज किया था। इसके तुरंत बाद अभियोजन पक्ष के गवाह –23 ने स्वयं अभियोजन पक्ष के गवाह –2 का बयान दर्ज किया और उस बयान में अपीलकर्ता का नाम उस व्यक्ति के रूप में उल्लेख किया गया था जिसे आखिरी बार मृतकों में से एक के साथ देखा गया था। अपीलकर्ता के वकील द्वारा आग्रह किया गया एक और तर्क यह है कि इस मामले में मृत व्यक्तियों को कई चोटें पहुंचाई गई थीं और लाठी, लकड़ी के मूसल, कुल्हाड़ी के टूटे हुए हैंडल, कैंची और 'कुंटा' का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया गया था और यह तर्क दिया गया था कि इन तथ्यों के आधार पर, यह संभव है कि एक से अधिक हमलावर रहे होंगे और इसलिए, अभियोजन पक्ष ने वास्तविक तथ्यों को छुपाया और अपीलकर्ता संदेह का लाभ पाने का हकदार है। कथित तौर पर अपीलकर्ता द्वारा अपराध के हथियार के रूप में इस्तेमाल की गई सभी वस्तुएं वे चीजें हैं जो घर से ही एकत्र की गई होंगी और अभियोजन पक्ष के अनुसार, अपीलकर्ता को शाम को मृतक जोरा राम के साथ देखा गया था और पूरी संभावना है कि उसने शिव प्रताप के घर रात बिताई होगी। घटना रात के अंधेरे में हुई होगी और सर्दी का मौसम होने के कारण बहुत संभव है कि पड़ोसियों का ध्यान आकर्षित नहीं हुआ होगा। यह तथ्य कि घरेलू वस्तुओं का उपयोग अपराध के हथियार के रूप में किया गया था, किसी बाहरी व्यक्ति की उपस्थिति की संभावना को खारिज करता है। चोटों की प्रकृति से यह भी अनुमान लगाना संभव नहीं है कि कितने हमलावर शामिल थे। यह काफी उचित और संभावित है कि एक हमलावर अकेले ही इतनी अधिक चोटें पहुंचा सकता है, खासकर रात के दौरान जब पीड़ित गहरी नींद में रहे होंगे।

अपीलकर्ता के वकील ने भी अपीलकर्ता के कहने पर की गई विभिन्न वसूलियों के बारे में गंभीर संदेह उठाया, लेकिन हमें अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं

मिला क्योंकि वसूली का समर्थन करने के लिए और भी पुष्ट सबूत हैं। ये वस्तुएं अपीलकर्ता के करीबी रिश्तेदार से बरामद की गईं और उनकी पहचान अभियोजन पक्ष के गवाह -17 द्वारा की गई। यह भी संदेह से परे स्थापित है कि बरामद खून से सनी शर्ट अपीलकर्ता की थी।

विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, हमें अभियुक्त के अपराध पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है क्योंकि यह साबित हो गया है कि अपीलकर्ता को 14 नवंबर, 1993 की शाम को एक मृतक जोरा राम के साथ देखा गया था और अपीलकर्ता का एक परिचित था मृतक के परिवार के सदस्यों के साथ क्योंकि वह पहले ही सुनार का व्यापार सीखने के लिए अभियोजन पक्ष के गवाह -17 की दुकान में प्रशिक्षु के रूप में काम कर चुका था। अभियोजन पक्ष के गवाह -17 ने बताया कि अपीलकर्ता को दुकान से भेज दिया गया था क्योंकि उसने सोने की कुछ छोटी चोरी की थी।

यह ध्यान रखना भी प्रासंगिक है कि गिरफ्तारी के समय अपीलकर्ता को कुछ चोटें आई थीं। ये चोटें मामूली प्रकृति की हैं, लेकिन फिर भी अपीलकर्ता इसके संबंध में कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। अपीलकर्ता के कहने पर विभिन्न वस्तुओं की बरामदगी, वह भी घटना के तुरंत बाद, अपीलकर्ता के अपराध को साबित करने में एक लंबा रास्ता तय करती है।

. हाल ही में अपराध किए जाने के बाद उसके फलों का कब्ज़ा, इस धारणा के लिए एक मजबूत और उचित आधार प्रदान करता है कि जिस पक्ष के कब्जे में वे पाए गए, वह असली अपराधी था, जब तक कि वह किसी तरह से इस तरह के कब्जे के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता। उनकी अनिच्छा या कोई उचित स्पष्टीकरण देने में असमर्थता को मजबूत, स्वयं दोषारोपण योग्य साक्ष्य के समान माना जाता है। यदि पक्ष उचित स्पष्टीकरण देता है कि उसने इसे कैसे प्राप्त किया, तो अदालतों के लिए अपराध का अनुमान न लगाना उचित होगा। अनुमान के इस नियम की शक्ति अपराध से संबंधित कब्जे की नवीनता पर निर्भर करती है और यदि समय का अंतराल काफी है, तो अनुमान कमजोर हो जाता है और विशेष रूप से, यदि सामान उस प्रकार का होता है जैसे सामान्य प्रक्रिया में होता है ऐसी चीजें बार-बार बदलती रहती हैं। कोई निश्चित अवधि निश्चित करना संभव नहीं है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में हत्या और डकैती के समान अनुमान लगाए हैं, खासकर जब आरोपी के पास ये आपत्तिजनक वस्तुएं पाई गईं और वह कोई उचित स्पष्टीकरण देने की स्थिति में नहीं था। *इयरभद्रप्पा @ कृष्णप्पा बनाम कर्नाटक राज्य,* [1983] 2 एससीसी 330 एक ऐसा मामला था जहां मृतक बचम्मा की गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी और अपीलकर्ता को हिरासत में ले लिया गया था और उसकी निशानदेही पर सोने के गहने और अन्य सामान बरामद किए गए थे। इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:

> यह एक ऐसा मामला है जहां हत्या और डकैती एक ही लेन-देन के अभिन्न अंग साबित होते हैं और इसलिए साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के उदाहरण (ए) के तहत उत्पन्न होने वाली धारणा यह है कि न केवल अपीलकर्ता ने मृतक की हत्या की है बल्कि उसके सोने के आभूषणों की डकैती भी की, जो उसी लेनदेन का हिस्सा थे।

[1997] 10 एससीसी 130 [*मुकुंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य*] में रिपोर्ट किए गए एक अन्य मामले में, अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि 17.1.1994 और 18.1.1994 की रात में, अपीलकर्ताओं ने एक अनुज प्रसाद दुबे के आवासीय घर में अतिक्रमण किया। अपनी पत्नी और उनके दो बच्चों की हत्या कर दी और उनके गहने और अन्य मूल्यवान सामान लूट लिया। अगली रात, अपीलकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया और पूछताछ की गई। एक आरोपी के बयान के आधार पर सोने और चांदी के आभूषण और अन्य सामान बरामद कर लिया गया। इस न्यायालय ने, *गुइब चंद बनाम एमपी राज्य* [1995] 3 एससीसी 574 में रिपोर्ट किए गए पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा:

"यदि मौजूदा मामले जैसे किसी दिए गए मामले में अभियोजन सफलतापूर्वक यह साबित कर सकता है कि डकैती और हत्या के अपराध एक ही लेनदेन में किए गए थे और उसके तुरंत बाद चोरी की संपत्ति बरामद कर ली गई थी, तो न्यायालय वैध रूप से न केवल एक अनुमान लगा सकती है तथ्य यह है कि जिस व्यक्ति के कब्जे में चोरी का सामान पाया गया, उसने न केवल डकैती की, बल्कि यह भी कि उसने हत्या भी की।"

मौजूदा मामले में, अपीलकर्ता यह स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि अभियोजन पक्ष के गवाह -17 और उसके परिवार के सदस्यों के विभिन्न सोने के गहने और अन्य सामान उसके कब्जे में कैसे आए। अपीलकर्ता यह भी कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दे सका कि उसके शरीर पर चोटें कैसे आईं और उसकी शर्ट खून से लथपथ कैसे हो गई। तथ्यों और परिस्थितियों में, यह एक उपयुक्त मामला है जहां साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के चित्रण (ए) के तहत अनुमान लगाया जा सकता है कि अपीलकर्ता ने हत्याएं और डकैती की। निचली अदालतों ने अपीलकर्ता को उसके खिलाफ लगाए गए अपराधों के लिए दोषी ठहराया है।

सजा के सवाल के संबंध में, अपीलकर्ता के वकील ने कहा कि अपीलकर्ता अपराध के समय 20 वर्ष का युवा था और जब से उसे मौत की सजा दी गई है, तब से वह विनाशकारी और अपमानजनक भय से ग्रस्त है। निंदा की गई और अपीलकर्ता तीव्र मानसिक पीड़ा से गुजर रहा होगा जो अनिवार्य रूप से मौत की सजा के तहत कारावास से जुड़ा है। यह प्रस्तुत किया गया है कि इन कारकों को इस न्यायालय द्वारा मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदलने के लिए प्रासंगिक कम करने वाले कारकों के रूप में ध्यान में रखा गया था।

बेशक, अपीलकर्ता द्वारा किए गए अपराध की प्रकृति बहुत भयानक और असाधारण रूप से क्रूर और परपीड़क थी। हालाँकि, हम मामले के विभिन्न तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक उदार दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक हैं। आपराधिक मामलों से निपटने में जहां अपराध के लिए सजा के रूप में मौत की सजा कानून में निर्धारित है, अदालतों को नई चुनौतियों का जवाब देने की आवश्यकता है क्योंकि उद्देश्य न केवल बड़े पैमाने पर समाज की रक्षा करना है, बल्कि उचित सजा देना भी है, ताकि आपराधिक न्याय वितरण प्रणाली में जनता के विश्वास को कम करने की प्रवृत्ति न हो।

ए देवेन्द्रन बनाम तमिलनाडु राज्य, [1997] 11 एससीसी 720 में, मृत्युदंड लगाने के सवाल पर विचार करते हुए, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया: - (परिच्छेद 26 में)

"उपरोक्त मामलों के तर्क को ध्यान में रखते हुए यह देखा जा सकता है कि चूंकि एक अनुमोदक के साक्ष्य को विचार से हटा दिया गया है, इसलिए धारा 302 के तहत अपीलकर्ता देवेंद्रन की सजा को अभियोजन पक्ष के गवाह-2, अभियोजन पक्ष के गवाह 5 और के साक्ष्य के आधार पर बरकरार रखा गया है। उक्त देवेन्द्रन के घर से हत्या के लिए इस्तेमाल की गई पिस्तौल की बरामदगी के साथ-साथ हिरासत में रहते हुए उसके बयान के आधार पर मुखबिर के आभूषण और अन्य आभूषणों की बरामदगी भी की गई। और उन गहनों की पहचान अभियोजन पक्ष के गवाह-4 द्वारा की जा रही है। उपरोक्त साक्ष्य बिना किसी कल्पना के मामले को दुर्लभतम मामलों में से एक बनाते हैं जहां मौत की चरम सजा दी जा सकती है।"

मौजूदा मामले में भी यही स्थिति है। ऊपर चर्चा किए गए परिस्थितिजन्य साक्ष्य, भले ही आरोपी को दोषी ठहराने के लिए विश्वसनीय माने जाते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि यह मौत की सजा देने वाले दुर्लभतम मामलों में से एक है।

अत: उचित सज़ा क्या होगी?

हमारे सामने आए अपराधों को समदृष्टि से नहीं देखा जा सकता क्योंकि वे जीवन में जो कुछ भी अच्छा है उसमें व्यक्ति का विश्वास नष्ट कर देते हैं। एक नवयुवक को स्वर्ण–कारी सीखने का अवसर दिया गया। एक बार उसे चोरी के कथित कृत्य के लिए बाहर भेज दिया गया था। फिर भी, घटना के दिन, उसे मृतक बूढ़े व्यक्ति के साथ जाने की अनुमति दी गई और सबूत के अनुसार, वह मृतक के साथ उसके घर में गया। उस दयालुता का प्रतिफल बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी सहित तीन बेटियों की हत्या है, जिनमें से एक की शादी दो महीने बाद तय हुई थी। इसलिए, भले ही हम मृत्युदंड को कम कर देते हैं, हम सोचते हैं कि सजा पर्याप्त होनी चाहिए ताकि निवारक प्रभाव हो और साथ ही आरोपी को अपराध में दोबारा शामिल होने और समाज के लिए खतरा बनने का कोई मौका न मिले।

धारा 57 आईपीसी में प्रावधान है कि सजा की शर्तों के अंशों की गणना में, आजीवन कारावास को बीस साल के कारावास के बराबर माना जाएगा। हमारी राय में, अभियुक्त द्वारा किए गए जघन्य बर्बर अपराध को देखते हुए, किसी भी परिस्थिति में अभियुक्त को 20 साल की सजा पूरी होने से पहले रिहा नहीं किया जाना चाहिए। इस न्यायालय ने *दलबीर सिंह और अन्य बनाम पंजाब राज्य,* [1979] 3 एससीसी 745 में इस प्रश्न पर विचार किया कि ऐसे मामले में जहां मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास कर दिया गया है, आरोपी को कितने वर्षों तक जेल में रखा जाना चाहिए। परिच्छेद 14 में न्यायालय ने इस प्रकार कहा:–

> "14. वर्तमान अपील में मौत की सजा को घटाकर आजीवन कारावास किया जा सकता है। हम *राजेंद्र प्रसाद* मामले में फैसले में एक पाद लेख जोड़ सकते हैं। उन्मूलन पर अंग्रेजी कानून से संकेत लेते हुए, हम सुझाव दे सकते हैं कि आजीवन कारावास जो कड़ाई से इसका मतलब है कि व्यक्ति के पूरे जीवन के लिए कारावास, लेकिन व्यवहार में यह 10 से 14 साल के बीच की अवधि के लिए कारावास के समान है, दोषी न्यायालय के विकल्प पर, इस शर्त के अधीन हो सकता है कि कारावास की सजा इतने लंबे समय तक रहेगी। जीवन वहां टिकता है जहां जानलेवा पुनरावर्तन के असाधारण संकेत होते हैं और समुदाय दोषी के बड़े पैमाने पर होने का जोखिम नहीं उठा सकता है। यह न्यायिक आशंकाओं का ख्याल रखता है कि जब तक शारीरिक रूप से समाप्त नहीं किया जाता, अपराधी किसी दूरस्थ समय में हत्या की पुनरावृत्ति कर सकता है।
>
> (जोर दिया गया)

सुभाष चंदर बनाम कृष्णलाल और अन्य, [2001] 3 स्केल 130 के मामले में, इस न्यायालय द्वारा उक्त सिद्धांत का पालन किया गया है और यह आदेश दिया गया था कि आरोपी को उसके शेष जीवन के लिए जेल में रखा जाएगा और और यह कि उसे समाज के लिए खुला नहीं छोड़ा जाएगा क्योंकि वह एक संभावित खतरा है।

सवाल उठ सकता है कि क्या सीआरपीसी की धारा 433–ए के साथ पठित धारा 433 (बी) के प्रावधान को देखते हुए आरोपी को 14 साल की सजा पूरी होने पर रिहा कर दिया जाना चाहिए? इस प्रयोजन के लिए, हम यह स्पष्ट कर देंगे कि धारा 433 (बी) के तहत उपयुक्त सरकार आजीवन कारावास, अधिकतम 14 वर्ष की कैद या जुर्माने की सजा को कम करने में सक्षम बनाती है। धारा 433–ए के तहत, यह प्रदान करके उस शक्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है कि जहां किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर आजीवन कारावास की सजा दी जाती है जिसके लिए मौत कानून के तहत प्रदान की गई सजाओं में से एक है, तो ऐसा व्यक्ति नहीं है। जेल से रिहा किया जाए जब तक कि वह कम से कम चौदह वर्ष कारावास की सजा न काट ले। इस प्रश्न पर इस न्यायालय और प्रिवी काउंसिल द्वारा दिए गए विभिन्न निर्णयों पर विचार किया गया है और यह दोहराया गया है कि प्रथम दृष्टया लगाए गए आजीवन कारावास की सजा को दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि के लिए कारावास के रूप में माना जाएगा। यह भी स्थापित कानून

है कि जेल अधिनियम के तहत बनाए गए नियम आजीवन कारावास की सजा के स्थान पर कम सजा नहीं देते हैं। *मध्य प्रदेश राज्य बनाम रतन सिंह और अन्य* में, न्यायालय, [1976] 3 एससीसी 470 परिच्छेद 4 और 9 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया गया: –

"4. जहां तक पहले बिंदु का संबंध है, अर्थात्, पंजाब जेल मैनुअल या जेल अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत 20 साल की समाप्ति पर कैदी को स्वचालित रूप से रिहा किया जा सकता है, मामला अब एकीकृत नहीं है और एक निष्कर्ष पर पहुंच गया है। *गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य*, [1961] 3 एससीआर 440 में इस न्यायालय का निर्णय, जहां न्यायालय ने, पं*डित किशोरी लाल बनाम राजा सम्राट* में प्रिवी काउंसिल के निर्णय के बाद, [(एलआर 72 आईए ।: एआईआर 1945) पीसी 64] इस प्रकार मनाया गया:

"उस धारा के तहत, उक्त धारा के अधिनियमन से पहले जीवन या किसी अन्य अवधि के लिए जेल भेजे गए व्यक्ति को आजीवन या उक्त अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा पाने वाले व्यक्ति के रूप में माना जाएगा।

यदि हां, तो अगला सवाल यह है कि क्या कानून में ऐसा कोई प्रावधान है जिसके तहत उचित सरकार द्वारा बिना किसी औपचारिक छूट के आजीवन कारावास की सजा को स्वचालित रूप से एक निश्चित अवधि के लिए एक सजा के रूप में माना जा सकता है। ऐसा कोई प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता या जेल अधिनियम में नहीं पाया जाता है।

* * * * *

आजीवन कारावास या आजीवन कारावास की सजा को प्रथम दृष्टया दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष अवधि के लिए परिवहन या कारावास के रूप में माना जाना चाहिए।

न्यायालय ने आगे इस प्रकार कहा:

लेकिन जेल अधिनियम किसी प्राधिकारी को सज़ा कम करने या कम करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है; यह केवल जेलों के विनियमन और उनमें बंद कैदियों के उपचार के लिए प्रावधान करता है। जेल अधिनियम की धारा 59 राज्य सरकार को अन्य बातों के साथ–साथ अच्छे आचरण के लिए पुरस्कार के लिए नियम बनाने की शक्ति प्रदान करती है। इसलिए अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों को अधिनियम के दायरे में ही समझा जाना चाहिए। उक्त नियमों के तहत धारा 401, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत एक उपयुक्त सरकार के आदेश, रिहाई के लिए एक शर्त हैं। हमारे ध्यान में कोई अन्य नियम नहीं लाया गया है जो जीवन भर के लिए परिवहन की सजा पाए कैदी को छूट सहित किसी विशेष अवधि की समाप्ति पर बिना शर्त रिहाई का अधिकार प्रदान करता हो। जेल अधिनियम के तहत नियम आजीवन कारावास की सजा के स्थान पर कम सजा नहीं देते हैं।

छूट का प्रश्न विशेष रूप से उपयुक्त सरकार के प्रांत के भीतर है; और इस मामले में यह स्वीकार किया गया है कि, हालांकि उपयुक्त सरकार ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत कुछ छूट दी है, लेकिन उसने पूरी सजा नहीं हटाई है। इसलिए, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता ने अभी तक रिहाई का कोई अधिकार हासिल नहीं किया है।

इसलिए, इस न्यायालय के निर्णय से यह स्पष्ट है कि जेल अधिनियम या जेल मैनुअल के तहत बनाए गए नियम कैदी को भुगतने की कुल अवधि को प्रभावित नहीं करते हैं, बल्कि दी जाने वाली

विभिन्न छूटों के संबंध में केवल प्रशासनिक निर्देश देते हैं। कैदी को समय-समय पर नियमानुसार। इस न्यायालय ने आगे बताया कि पूरी सजा या उसके एक हिस्से की माफी का सवाल आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 401 के तहत उपयुक्त सरकार के विशेष क्षेत्र में आता है और न ही भारतीय दंड संहिता की धारा 57 और न ही कोई नियम या स्थानीय अधिनियम भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा के प्रभाव को ख़राब कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, इस न्यायालय ने स्पष्ट रूप से माना है कि आजीवन कारावास की सजा आरोपी के जीवनकाल तक सुनिश्चित की जाएगी क्योंकि किसी विशेष अवधि को तय करना संभव नहीं है, नियमों के तहत कैदी की मृत्यु और छूट को आजीवन परिवहन की सज़ा के विकल्प के रूप में नहीं माना जा सकता है।

मर्ज़ी राम बनाम भारत संघ, [1981] 1 एससीसी 107 में, इस न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उपरोक्त स्थिति दोहराई और कहा कि अपरिहार्य निष्कर्ष यह है कि चूंकि धारा 433-ए में हम केवल आजीवन कारावास की सजा से निपटते हैं, छूट कहीं नहीं जाती है और किसी कैदी को रिहा करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। इसके अलावा, *लक्ष्मण नस्कर (जीवन दोषी) बनाम पश्चिम बंगाल राज्य* में और दूसरा [2000] 7 एससीसी 626, *गोपाल विनायक गोडसे बनाम महाराष्ट्र राज्य,* [1961] 3 एससीआर 440 के मामले के फैसले का जिक्र करने के बाद, न्यायालय ने दोहराया कि "आजीवन कारावास" की सजा का मतलब आम तौर पर कारावास होता है। दोषी व्यक्ति के प्राकृतिक जीवन की शेष पूरी अवधि; इस तरह की सज़ा काट रहा एक दोषी जेल नियमों के तहत अपनी सज़ा के कुछ हिस्से में छूट प्राप्त कर सकता है, लेकिन इस धारा के तहत उसकी पूरी सजा को माफ करने के लिए उपयुक्त सरकार के आदेश के अभाव में ऐसी छूट दोषी को स्वचालित रूप से, पूर्ण जीवन अवधि पूरी होने से पहले, रिहा होने का अधिकार नहीं देती है। यह देखा गया कि हालांकि प्रासंगिक नियमों के तहत, आजीवन कारावास की सजा 20 साल की निश्चित अवधि के बराबर होती है, लेकिन ऐसे कैदी को छूट सहित ऐसी विशेष अवधि की समाप्ति पर बिना शर्त रिहा करने का कोई अपरिहार्य अधिकार नहीं है। यह केवल उन छूटों को पूरा करने के उद्देश्य से है कि उक्त सजा निश्चित अवधि के बराबर है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं।

इसलिए, न्याय के हित में, हम अपीलकर्ता को दी गई मौत की सजा को कम करते हैं और निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को आजीवन कारावास की सजा भुगतनी होगी। हम आगे निर्देश देते हैं कि अपीलकर्ता को जेल से तब तक रिहा नहीं किया जाएगा जब तक कि उसने कम से कम 20 साल की सजा नहीं काट ली हो, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा पहले से ही भुगती गई अवधि भी शामिल है। जहां तक आईपीसी की धारा 392 और 397 के तहत अपराधों का संबंध है, हम अपीलकर्ता की दोषसिद्धि की पुष्टि करते हैं और कोई अलग सजा नहीं दी गई है।

उपरोक्त निर्देशों एवं सजा में संशोधन के साथ अपील का निस्तारण किया जाता है।

के.टी. अपील निस्तारित

विक्रांत ठाकुर की देखरेख में सुमीत कपूर द्वारा अनुवादित।